प्रकाशकुमार @ प्रकाश भुट्टो

बनाम

गुजरात राज्य

12 जनवरी, 2005

[मुख्य न्यायाधीश, आर.सी. लाहोटी, बी.एन. अग्रवाल, एच.के. सेमा, जी.पी. माथुर

और पी.के. बालासुब्रमण्यन, न्यायाधिपतिगण]

आतंकवादीऔरविघटनकारीगतिविधियाँ(रोकथाम) अधिनियम, 1987:

धारा15 और 12–टाडा सहित किसी भी अन्य कानून के तहत अपराध के परीक्षण – टाडा की धारा 15 के तहत दर्ज की गई स्वीकारोक्ति की स्वीकार्यता, यदि आरोपी उसी मुकदमे में टीएडीए के तहत अपराध से बरी हो जाता है, तो यह जारी रहेगा किसी भी अन्य कानून के तहत उन अपराधों के लिए स्वीकार्य रहेगा जिनकी सुनवाई टाडा अपराधों के साथ की गई थी।

धारा 12 – टाडा के तहत अन्वीक्षा – साधारण प्रक्रियात्मक कानून की अनुपलब्धता – अभिनिर्धारित किया, भेदभावपूर्ण नहीं – टाडा के तहत मुकदमा चलाने वाले व्यक्तियों को एक अलग वर्ग का गठन किया जाता है – अपराधों की गंभीर और क्रोधित प्रकृति के लिए उन पर मुकदमा चलाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया अलग–अलग वर्गीकरण के तहत होती है – भारत का संविधान, 1950 – अनुच्छेद 14 और 21।

धारा 18 – मामलों को नियमित अदालतों में स्थानांतरित करने के लिए आह्वान – माना जाता है कि प्रावधान केवल उस चरण में लागू किया जा सकता है जहां नामित न्यायालय संज्ञान लेता है, यानी जांच पूरी होने और आरोप पत्र दायर होने के बाद।

अधिनियम का दुरुपयोग – पुलिस अधिकारियों के साथ–साथ नामित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के खिलाफ सावधानी – अधिनियम को प्रभावी ढंग से और विधायी इरादे के अनुरूप लागू करने के लिए यानी दिमाग लगाने के बाद।

क़ानून की व्याख्या – किसी क़ानून की व्याख्या करने के लिए न्यायालय का क्षेत्राधिकार केवल अस्पष्टता के मामले में ही लागू किया जा सकता है।

शब्द और वाक्यांश– "लेकिन इस धारा के प्रावधानों के अधीन"और "इस अधिनियम के तहत अपराध के लिए" – आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 15 के संदर्भ में, इसका अर्थ

राज्य बनाम नलिनी, [1999] 5 एससीसी 253] में आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1987 (टीएडीए) की धारा 15 के संदर्भ में एक बयान की स्वीकार्यता के संबंध में निर्णय की शुद्धता पर संदेह, इस न्यायालय की दो–न्यायाधीशों की पीठ ने मामले को तीन–न्यायाधीशों की पीठ के पास भेज दिया, जिसने बदले में फैसला सुनाया। यह संदर्भ पांच न्यायाधीशों की पीठ का है।

निर्धारण के लिए प्राथमिक प्रश्न यह है कि क्या टाडा की धारा 15 के तहत विधिवत दर्ज किया गया इकबालिया बयान किसी अन्य कानून के तहत उन अपराधों के लिए स्वीकार्य बना रहेगा, जिनकी सुनवाई अधिनियम की धारा 12 के तहत टाडा अपराधों के साथ की गई थी, इसके बावजूद तथ्य यह है कि उक्त मुकदमे में आरोपी को टाडा के तहत अपराध से बरी कर दिया गया था।

संदर्भ का उत्तर देते हुए, न्यायालय

अभिनिर्धारित किया: 1.1. आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1987 (टाडा), हालांकि एक लघु कानून है, लेकिन आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए बहुत कठोर और उग्र प्रावधानों से युक्त है। [415–एचजे)

> करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य, [1994] 3 एससीसी 569 और हितेंद्र विष्णु ठाकुर बनाम महाराष्ट्र राज्य, [1994] 4 एससीसी 602, का उल्लेख किया गया है।

प्रदीप चंद्र परीजा बनाम प्रमोद चंद्र पटनायक, [2002] 1 एससीसी 1, उद्धृत किया गया।

1.2. कानून जितना सख्त होगा, न्यायालय का विवेक उतना ही कम होगा। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कड़े कानून बनाये जाते हैं। यह विधायिका का इरादा होने के नाते न्यायालय का कर्तव्य है कि वह यह देखे कि विधायिका का इरादा विफल न हो। [422–जी–एच]

बिलाल अहमद कालू बनाम स्टेट ऑफ ए.पी., [1997] 7 एससीसी 431, खारिज कर दिया गया।

रामभाई नाथाभाई गढ़वी बनाम गुजरात राज्य, [1997] 7 एससीसी 744 और गुरप्रीत सिंह बनाम पंजाब राज्य, [2002] 10 एससीसी 201, अभिनिर्धारित, पर इन्क्यूरियम,

स्वीडिश मैच एबी और अन्य बनाम प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारत और अन्य, (2004) 7 स्केल 158, पर निर्भर।

2.1. किसी क़ानून की व्याख्या करने का न्यायालय का अधिकार क्षेत्र केवल अस्पष्टता की स्थिति में ही लागू किया जा सकता है। जब क़ानून की भाषा सीधी और स्पष्ट हो तो न्यायालय कानून या इरादे का दायरा नहीं बढ़ा सकता। [426–सी]

नसीरुद्दीन बनाम सीता राम अग्रवाल, [2003] 2 एससीसी 577; मोहन कुमार सिंघानिया बनाम भारत संघ, [1992] पूरक 1 एससीसी 594 और बलराम कुमावत बनाम भारत संघ, [2003] 7 एससीसी 628, –भरोसा व्यक्त किया गया।

सुपरिंटेंडेंट एंड रिमेंबरेंसर ऑफ लगल अफेयर्स टू गर्वनमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम आबानी मैटी, [1979] 4 एससीसी 85, उद्धृत।

2.2. टाडा अधिनियम की धारा 15 और उसके तहत बनाए गए नियम अपने आप में एक स्व–निहित कोड है, जो प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय प्रदान करता है और इसमें प्रयुक्त शब्द "लेकिन इस धारा के प्रावधानों के अधीन"का अर्थ धारा के तहत निर्धारित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय होगा। धारा 15 का साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता पर अधिभावी प्रभाव है, स्वीकारोक्ति दर्ज करने में पालन की जाने वाली एकमात्र प्रक्रिया धारा 15 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया है। धारा 15(1) में "लेकिन इस धारा के प्रावधानों के अधीन"शब्दों को शामिल करते समय विधान का यही एकमात्र उद्देश्य होगा। [430–एच; 431–ए–बी]

2.3 जहां तक धारा 15 में प्रयुक्त "इस अधिनियम के तहत अपराध के लिए"शब्दों का संबंध है, धारा 15(1) में संदर्भित 'अधिनियम'शब्द अधिनियम की धारा 12 से संबंधित है। इसलिए धारा 15 को धारा 12 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। [431–बी]

2.4. धारा 12 और 15 को समग्र रूप से पढ़ने से कोई संदेह नहीं रह जाता है कि एक प्रावधान को दूसरे प्रावधान के संदर्भ में समझा जाना चाहिए और इसके विपरीत ताकि प्रावधान को प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के अनुरूप बनाया जा सके। [432–डी–ई]

भारतीय रिज़र्व बैंक बनाम पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, [1987] 1 एससीसी 424 और अनवर हसन खान बनाम मोहम्मद शफी और अन्य, [2001] 8 एससीसी 540, भरोसा व्यक्त किया।

2.5. धारा 12(1) और (2) में अंतर्निहित विधायी मंशा स्पष्ट रूप से समझ में आती है, नामित न्यायालय को अधिनियम के तहत किए गए अपराधों के साथ–साथ किसी अन्य कानून के तहत किए गए अपराधों के लिए अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने और उन्हें दोषी ठहराने का अधिकार देना, यदि अपराध इस तरह अन्य अपराध से जुड़ा हुआ है। अधिनियम की धारा 12(1) में प्रयुक्त भाषा, "यदि अपराध ऐसे अन्य अपराध से जुड़ा है"का बहुत महत्व है। आवश्यक परिणाम यह है कि एक बार जब अन्य अपराध टाडा के तहत अपराध से जुड़ा होता है और यदि आरोपी पर संहिता के तहत आरोप लगाया जाता है और एक ही अन्वीक्षा में एक साथ मुकदमा चलाया जाता है, तो नामित न्यायालय को आरोपी को इस तथ्य के बावजूद कि टाडा के तहत कोई अपराध नहीं बनता है, किसी अन्य कानून के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराने के लिए अधिकार है। यह विधायिका का एकमात्र उद्देश्य हो सकता है। अन्यथा मानने का मतलब होगा कि कानून को दोबारा लिखना या नया स्वरूप देना और उसमें कुछ ऐसा पढ़ना जो वहां नहीं है। (433–सी–ईजे)

3.1. यह तर्क कि धारा 12 की कठोरता भेदभावपूर्ण है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के क्रोध को आकर्षित करती है क्योंकि यह नामित न्यायालय को टाडा के तहत किए गए अपराधों के साथ–साथ किसी अन्य कानून के तहत किए गए अपराधों के लिए अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने और उन्हें दोषी ठहराने का अधिकार देती है। जिससे सामान्य कानून के तहत आरोपी को उपलब्ध अधिकारों से वंचित किया जाना गलत धारणा है। [433–एफ]

3.2. अनुच्छेद 14 भेदभाव पर रोक लगाता है, लेकिन प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ संबंध रखते हुए, समझदार अंतर के आधार पर उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है। धारा 12 को लागू करने से जो उद्देश्य प्राप्त करने का प्रयास किया गया है वह आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े या उनके आनुषंगिक अपराध को ध्यान में रखना है, अन्य अपराध जो आतंकवादी अधिनियम से जुड़े हुए हैं और अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। 1433–एफ–जी]

3.3. टाडा के तहत मुकदमे का विचारण सामान्य कानून से अलग है। जिन व्यक्तियों पर टाडा के प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाता है, वे व्यक्तियों का एक अलग वर्ग हैं और अपराधों की गंभीर और कुपित प्रकृति के लिए उन पर मुकदमा चलाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया सामान्य अपराधियों और प्रक्रिया से अलग वर्गीकरण के तहत होती है। अभियुक्तों के समूहीकरण और टाडा के तहत विचारणीय अपराधों का यह भेद और वर्गीकरण अधिनियम के सार्थक उद्देश्य और वस्तु को प्राप्त करने के लिए है जैसा कि प्रस्तावना के साथ–साथ वस्तुओं और कारणों के कथन से परिलक्षित होता है। [433–एच; 434–ए)

करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य, [1994] 3 एससीसी 569, पर भरोसा किया गया।

4. टाडा की धारा 15 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत विधिवत दर्ज किया गया इकबालिया बयान किसी भी अन्य कानून के तहत अपराधों के लिए स्वीकार्य बना रहेगा, जिसकी सुनवाई अधिनियम की धारा 12 के तहत टाडा अपराधों के साथ की गई थी, भले ही आरोपी को उसी मुकदमे में TADA के तहत अपराधों से बरी कर दिया गया हो। [434–सी–डी]

राज्य बनाम नलिनी, [1999] 5 एससीसी 253, पुष्टि की गई।

5.1. यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिनियम की धारा 18 में प्रयुक्त शब्द, "संज्ञान लेने के बाद"इसमें मुकदमे का कोई भी चरण शामिल होगा जिसमें वह चरण भी शामिल होगा जब फैसला सुनाया जाना है। यदि विधायिका की यही मंशा होती तो वे ऐसा कह सकते थे। विधायिका जानबूझकर "किसी भी अपराध का संज्ञान लेने के बाद"शब्दों का उपयोग करती है, जिसका अर्थ है कि धारा 18 केवल उस चरण पर लागू होगी जहां नामिंत न्यायालय अपराध का सज्ञान लेता है, यानी जांच पूरी होने और आरोप पत्र दायर होने के बाद। धारा 18 में प्रयुक्त भाषा में कोई अस्पष्टता नहीं है। [434–जी–एच; 435–सी

5.2. सीआरपीसी की धारा 209 के प्रावधान जिस पर अपीलकर्ताओं ने भरोसा करने की मांग की, वह धारा 18 के अनुरूप नहीं है। धारा 209 सीआर.पी.सी. में, "संज्ञान लेने के बाद"शब्द स्पष्ट रूप से अनुपस्थित हैं। धारा 18 एक फ़िल्टर्ड प्रावधान है जो केवल उस चरण में लागू होता है जब नामिंत न्यायालय अपराध का सज्ञान लेता है। 1434–एच; 435–एजे

6. करतार सिंह के मामले में इस न्यायालय द्वारा दी गई चेतावनी का नोट पुलिस अधिकारियों के साथ–साथ नामित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को अधिनियम का दुरुपयोग करने से सावधान करने और अधिनियम को प्रभावी ढंग से और विधायी मंशा के अनुरूप जिसका अर्थ विवेक के प्रयोग के बाद होगा। 1435–सी, एच; 436–ए]

करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य, [1994] 3 एससीसी 569, पुष्टि की गई।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 526/2001

आतंकवादी आपराधिक प्रकरण संख्या 2/1997 में नामित न्यायालय संख्या 3, अहमदाबाद के निर्णय और आदेश दिनांक 19.3.2001 से।

आपराधिक अपील क्रमांक 526/2001, में अपीलकर्ता के लिए मनीष सिंघवी, सौरभ, अजय और अशोक के. महाजन।

आपराधिक अपील क्रमांक 545/2001, में अपीलकर्ता के लिए सुशील कुमार, एडॉल्फ मैथ्यू, पुनीत राय, विनय अरोड़ा और संजय जैन।

आपराधिक अपील क्रमांक 665/2001 में अपीलकर्ता के लिए सुश्री आशा जी. नायर और सुश्री अनु मोहला।

प्रतिवादी की ओर से यशांक अध्यारु, सुश्री हेमन्तिका वाही और सुश्री अरुणा गुप्ता।

न्यायालय का निर्णय एच.के; सेमा, न्यायाधिपति द्वारा सुनाया गया। ये सभी अपीलें आतंकवादी प्रकरण संख्या 2/1997, आतंकवादी प्रकरण संख्या 33 /1994 और आतंकवादी प्रकरण संख्या 16/1995 में अहमदाबाद में नामित न्यायालय संख्या 3 द्वारा पारित 19 मार्च 2001 के फैसले और आदेश के खिलाफ निर्देशित हैं। दो–न्यायाधीशों की पीठ, जिसके समक्ष ये अपीलें सुनवाई के लिए लगाई गई थीं, ने दिनांक 24.9.2002 के एक आदेश द्वारा मामलों को तीन–न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया। उक्त आदेश इस प्रकार है:–

> "इस मुद्दे में आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1987 (संक्षेप में "टाडा अधिनियम") की धारा 15 के संदर्भ में एक स्वीकारोक्ति की स्वीकार्यता के संदर्भ में है। नतीजतन, इसलिए, धारा 12 और 18 में निहित अन्य प्रावधान इसमें विधायी मंशा का आकलन करने के लिए इसे पढ़ा जाना चाहिए।
>
> राज्य बनाम नलिनी, [1999] 5 एससीसी 253 में इस न्यायालय ने पैराग्राफ 80 और 81 में कानून को इस प्रकार बताया: –
>
> "80. टाडा की धारा 12 निर्दिष्ट न्यायालय को आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार टाडा के तहत किसी भी अपराध के साथ–साथ किसी भी अन्य अपराध "जिसके लिए आरोपी पर आरोप लगाया जा सकता है"की संयुक्त रूप से सुनवाई करने में सक्षम बनाती है। उप–धारा (2) यह नामित न्यायालय को ऐसे मुकदमे में अभियुक्त को "किसी अन्य कानून के तहत"किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराने का अधिकार देता है, यदि ऐसे मुकदमे में नामित न्यायालय द्वारा यह पाया जाता है कि अभियुक्त को ऐसे अपराध का दोषी पाया गया है। यदि अभियुक्त ऐसे मुकदमे में टाडा के तहत अपराध से बरी कर दिया जाता है, लेकिन

किसी अन्य कानून के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि किसी अन्य कानून के तहत ऐसे अन्य अपराध के लिए ही मुकदमा था।

81. टाडा की धारा 15 किसी अभियुक्त द्वारा उसमें निर्दिष्ट पुलिस अधिकारी को दिए गए इकबालिया बयान को "ऐसे व्यक्ति के मुकदमे में"स्वीकार्य बनाने में सक्षम बनाती है। इसका मतलब है, अगर टाडा के तहत किसी भी अपराध का मुकदमा किसी अन्य कानून के तहत किसी अन्य अपराध के साथ चल रहा था, तो इकबालिया बयान की स्वीकार्यता तब भी कायम रहेगी, भले ही आरोपी टाडा अपराधों के तहत बरी कर दिया गया हो।"

ऊपर व्यक्त दृष्टिकोण अनुच्छेद 408 और 674 में व्यक्त दृष्टिकोण के साथ मेल खाता है और इसे नीचे इस प्रकार देखा गया है:–.

"408. वर्तमान मामले में टाडा की धारा 3 या धारा 4 के तहत कोई अपराध बनता है या नहीं, इस पर हम फैसले के बाद के चरण में विचार करेंगे। बिलाल अहमद कालू प्रकरण में इस न्यायालय के फैसले के मद्देनजर, श्री नटराजन का तर्क काफी हद तक सही है। हालाँकि, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि जब आरोपी को टाडा की धारा 3 या धारा 4 के तहत अपराधों से बरी कर दिया जाता है, तो मुकदमे में स्वीकारोक्ति को अस्वीकार्य मानते हुए, टाडा की धारा 12 के प्रावधानों को इस न्यायालय द्वारा उक्त निर्णय में ध्यान में नहीं रखा गया था। धारा 12 इस प्रकार है:

"12. अन्य अपराधो के संबंध में नामित न्यायालयों की शक्ति–

(1) किसी भी अपराध की सुनवाई करते समय, एक नामित न्यायालय किसी अन्य अपराध की भी सुनवाई कर सकता है, जिसके लिए संहिता के तहत आरोपी पर उसी मुकदमे में आरोप लगाया जा सकता है, यदि अपराध ऐसे अन्य अपराध से जुड़ा हो।

(2) यदि, इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के मुकदमे के दौरान, यह पाया जाता है कि आरोपी व्यक्ति ने इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए किसी नियम या किसी अन्य कानून के तहत कोई अन्य अपराध किया है, तो नामित न्यायालय ऐसे व्यक्ति को दोषी ठहरा सकता है। ऐसे अन्य अपराध का व्यक्ति और इस अधिनियम या ऐसे नियम द्वारा द्वारा अधिकृत कोई भी सजा पारित करें, जैसा भी मामला हो, ऐसे अन्य कानून द्वारा,उसके दण्ड के लिए।"

"674. टाडा अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, धारा 15 के तहत दर्ज की गई स्वीकारोक्ति टाडा अधिनियम या बनाए गए नियमों के तहत अपराध के लिए किसी व्यक्ति, सह–अभियुक्त, उकसाने वाले या साजिशकर्ता के मुकदमे में स्वीकार्य होगी। इसके तहत और ऐसे अन्य अपराध जिसके लिए ऐसे व्यक्ति पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत एक ही मुकदमे में आरोप लगाया जा सकता है, बशर्ते टाडा अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत अपराध ऐसे अन्य अपराध से जुड़ा हो।"

हालाँकि, हम नलिनी (उपरोक्त) में इस न्यायालय की 3–न्यायाधीश पीठ द्वारा घोषित कानून की स्थिति के संबंध में अपने संदेह को दर्ज करने के लिए बाध्य हैं।

इसलिए, मुद्दा यह है कि क्या इकबालिया बयान तब भी प्रभावी रहेगा, जब आरोपी को टाडा अपराधों के तहत बरी कर दिया जाता है और यह स्पष्ट निष्कर्ष है कि टाडा अधिनियम का गलत तरीके से सहारा लिया गया है या अधिनियम के तहत बयान अपनी कानूनी प्रभावकारिता खो देता है और इस प्रकार यह देश के सामान्य कानून के तहत पुलिस के समक्ष एक सामान्य इकबालिया बयान बन जाता है। नलिनी (सुप्रा),हालाँकि, जैसा कि ऊपर देखा गया है, इसका उत्तर सकारात्मक रूप में है, लेकिन हमें इससे संबंधित कुछ संदेह हैं क्योंकि संपूर्ण न्याय वितरण प्रणाली निष्पक्षता की अवधारणा पर निर्भर है: यह न्याय का हित है जिसकी देश के आपराधिक न्यायशास्त्र में प्रमुख भूमिका है। देश में न्याय की पहचान आज की मांग और समय की मांग है। एक बार जब न्यायालय इस निश्चित निष्कर्ष पर पहुंच जाता है कि टाडा अधिनियम लागू करना पूरी तरह से अनुचित है या टाडा के तहत फंसाने के लिए पूरी तरह से तुच्छता है, तो क्या यह उचित होगा कि धारा 15 को टाडा मामलों की तरह समान बल के साथ लागू किया जाएगा ताकि अपराधियों के खिलाफ देश के सामान्य कानून के तहत मामला दर्ज किया जा सके। जैसा कि ऊपर देखा गया है, इस प्रकार संदेह है।

उपरोक्त के मद्देनजर और प्रदीप चंद्र परीजा बनाम प्रमोद चंद्र पटनायक, [2002] 1 एससीसी 1 में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले को ध्यान में रखते हुए, इस उद्देश्य के लिए हम इस मामले को 3–न्यायाधीशों की पीठ का गठन करने के लिए भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने के लिए रजिस्ट्री को निर्देश देना उचित समझते हैं। यह तदनुसार आदेश दिया गया है।"

बदले में, तीन–न्यायाधीशों की पीठ ने दिनांक 9.3.2004 के एक आदेश द्वारा मामलों को पांच–न्यायाधीशों की पीठ को भेज दिया है। आदेश इस प्रकार है:–

> "यह मामला राज्य बनाम नलिनी, [1999] 5 एससीसी 253 में आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम, 1987 की धारा 15 के संदर्भ में एक स्वीकारोक्ति की स्वीकार्यता के निर्णय की शुद्धता पर संदेह करते हुए 3–न्यायाधीशों की पीठ को भेजा गया है। यह कहा गया है कि आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम (पोटा) के तहत भी समान प्रावधान उपलब्ध हैं। यदि वास्तव में 2–न्यायाधीशों की पीठ द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिया जाना है, तो यह केवल एक पीठ द्वारा ही किया जा सकता है। नलिनी के मामले (उपरोक्त) का निर्णय 5 न्यायाधीशों की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा किया गया है। इसलिए, यह मामला 5–न्यायाधीशों की पीठ को भेजा जाता है। रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि वह कागजात को उचित आदेश के लिए भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखे।"
>
> इस तरह से इस बेंच के सामने मामले रखे गए हैं।

आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1987 (इसके बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) विधान का एक हिस्सा है जिसमें 30 धाराएं हैं। हालांकि यह छोटा कानून है, लेकिन यह अधिनियम बहुत ही कठोर और सख्त है, जिसमें आतंकवाद के खतरे से निपटने के लिए कड़े प्रावधान शामिल हैं, जिसने बेतहाशा हत्याओं, आगजनी और संपत्ति की लूटपाट, मानवाधिकार को प्रभावित करते हुये अन्य घृणित अपराध और व्यक्तिगत छूट को बढ़ावा देते हुए एक स्थानिक रूप ले लिया है। अधिनियम की संवैधानिकता इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य, [1994] 3 एससीसी 569 में निष्कर्ष निकाला गया है। अधिनियम की धारा 15 की वैधता जो वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक होगी, संविधान के अधिकार के भीतर अभिनिर्धारित किया गया है। पैराग्राफ 217, 218, 220, 222, 236 और 243 में कहा गया है:

> "217. यदि प्रक्रियात्मक कानून दमनकारी है और संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करते हुए न्यायसंगत और निष्पक्ष सुनवाई के सिद्धांत का उल्लंघन करता है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाले कानूनों के समान संरक्षण का भेदभावपूर्ण उल्लंघन करता है, तो टाडा अधिनियम की धारा 15 को रद्द किया जाना चाहिए । इसलिए, 'अपराधियों'और 'अपराधों'के वर्गीकरण की जांच करना अनिवार्य रूप से आवश्यक हो गया है ताकि हमें यह

निर्णय लेने में सक्षम बनाया जा सके कि धारा 15 संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है या नहीं।

218. विधायी वर्गीकरण का सिद्धांत एक स्वीकृत सिद्धांत है जिसके तहत व्यक्तियों को समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है और ऐसे अंतर या भेद के लिए उचित आधार होने पर ऐसे समूहों के साथ अलग–अलग व्यवहार किया जा सकता है। भेदभाव का नियम यह है कि अलग–अलग परिस्थितियों में अलग–अलग व्यक्तियों या चीजों के बीच अंतर करने वाले कानून बनाने में, जो व्यक्तियों या वस्तुओं के एक समूह को नियंत्रित करते हैं, ऐसे कानून आवश्यक रूप से व्यक्तियों या वस्तुओं के दूसरे समूह को नियंत्रित करने वाले कानूनों के समान नहीं हो सकते हैं, इसलिए असमान व्यवहार का प्रश्न उठता है। यह वास्तव में विभिन्न स्थितियों और परिस्थितियों के विभिन्न सेट द्वारा शासित व्यक्तियों के बीच उत्पन्न नहीं होता है।

220. टाडा अधिनियम में किए गए भेद की बात करें तो आतंकवादियों और विघ्न डालने वालों को सामान्य कानूनों के तहत सामान्य अपराधियों से अपराधियों के एक अलग वर्ग के रूप में समूहित किया गया है और टाडा अधिनियम के तहत अपराधों का वर्गीकरण सामान्य अपराधों से अलग अपराधों के गंभीर रूप के रूप में किया जाना है। परीक्षण किया गया और निर्धारित किया गया कि क्या यह भेद और वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 की शर्तों के भीतर उचित और वैध है। भेद और वर्गीकरण की तर्कसंगतता के प्रश्न पर विचार करने के लिए, ऐसे भेद और वर्गीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखना आवश्यक है, जिसे निश्चित रूप से गणितीय परिशुद्धता के साथ बनाने की आवश्यकता नहीं है। यह पर्याप्त है कियदि व्यक्तियों और चीजों को एक साथ समूहीकृत किया गया है और समूहों से बाहर छोड़ दिए गए लोगों के बीच बहुत कम या कोई अंतर नहीं है, तो वर्गीकरण को उचित नहीं कहा जा सकता है। वर्गीकरण बनाने में, विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए और जांच की जानी चाहिए कि क्या ऐसा भेद या वर्गीकरण अलग–अलग उपचार को उचित ठहराता है और क्या वे प्राप्त की जाने वाली वस्तु की पूर्ति करते हैं।

222. जैसा कि ऊपर बताया गया है, जिन व्यक्तियों पर टाडा अधिनियम के प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाना है, वे व्यक्तियों का एक अलग वर्ग हैं और सामान्य अपराधियों और प्रक्रियाओं से अलग अलग वर्गीकरण के तहत अपराधों की गंभीर और बढ़ी हुई प्रकृति के लिए उन पर मुकदमा चलाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया।

अभियुक्तों के समूह का यह भेद और वर्गीकरण और टाडा के तहत मुकदमा चलाए जाने वाले अपराध अधिनियम के सार्थक उद्देश्य और उद्देश्य को प्राप्त करना है, जैसा कि प्रस्तावना के साथ–साथ 'उद्देश्यों और कारणों के विवरण'से परिलक्षित होता है, जिसके बारे में इस निर्णय के पूर्ववर्ती भाग में हमने विस्तार से बताया है।

236. उपरोक्त प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए, हमें यह तय करना होगा कि क्या 1987 अधिनियम (टाडा) की धारा 15 के प्रावधान अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं। सच है, यदि वर्गीकरण मनमाना और अनुचित और बिना किसी ठोस आधार के दिखाया गया है, तो कानून अनुच्छेद 14 द्वारा कानूनों के समान संरक्षण के विपरीत होगा ।

243. हमारे विचार में, उपरोक्त निर्णय का लाभ टाडा अधिनियम की धारा 15 को रद्द करने के लिए नहीं किया जा सकता क्योंकि 'अपराधियों'और 'अपराधों'का वर्गीकरण टाडा अधिनियम के तहत नामित न्यायालय द्वारा या विशेष न्यायालयों द्वारा किया जाना है। 1984 के अधिनियम को केंद्र सरकार के मनमाने और अनियंत्रित विवेक पर नहीं छोड़ा गया है, बल्कि अधिनियम ने ही अपराधियों का टाडा अधिनियम में आतंकवादी और विघटनकारी के रूप में और विशेष अदालत अधिनियम, 1984 के तहत आतंकवादी के रूप में और साथ ही दोनों अधिनियमों के तहत अपराधों का वर्गीकरण कर दिया है।

इस न्यायालय ने अनुच्छेद 259 में स्वीकारोक्ति दर्ज करने के तरीके के संबंध में पुलिस अधिकारी द्वारा अपनाए जाने वाले प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की ओर भी इशारा किया। फिर इसे पैराग्राफ 260 (एससीसी पृष्ठ 681) में निम्नानुसार रखा गया है: –

"260.उपरोक्त चर्चा के लिए, हम मानते हैं कि धारा 15 रद्द किए जाने योग्य नहीं है क्योंकि वह धारा संविधान के अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं करती है।"

हालाँकि, इस न्यायालय ने अत्यधिक सावधानी बरतते हुए कुछ दिशानिर्देश निर्धारित किए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्राप्त स्वीकारोक्ति किसी भी बुराई से दूषित नहीं है और फिर पैराग्राफ 263 (एससीसी पृष्ठ 682) में निम्नानुसार कहा गया है –

"263. हालाँकि, हम निम्नलिखित दिशानिर्देश बनाना चाहेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पुलिस अधीक्षक से कम रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा अभियोग–पूर्व पूछताछ में प्राप्त स्वीकारोक्ति किसी भी दोष से दूषित नहीं है, बल्कि सख्त है अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त और स्वीकृत सौंदर्य सिद्धांतों और मौलिक प्रसिद्धि के अनुरूप है।

(1) स्वीकारोक्ति को स्वतंत्र वातावरण में उसी भाषा में दर्ज किया जाना चाहिए जिसमें व्यक्ति की जांच की गई है और जैसा उसने बताया है;

(2) जिस व्यक्ति से अधिनियम की धारा 15(1) के तहत इकबालिया बयान दर्ज किया गया है, उसे मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना चाहिए, जिसके पास नियम 15(5) के तहत बयान बिना किसी अनुचित देरी के यांत्रिक उपकरण पर लिखित या रिकॉर्ड किए गए स्वीकारोक्ति के मूल बयान के साथ भेजना आवश्यक है;

(3) मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अभियुक्त द्वारा दिए गए बयान, यदि कोई हो, को ईमानदारी से दर्ज करना चाहिए और उसके हस्ताक्षर लेने चाहिए और यातना की किसी भी शिकायत के मामले में, व्यक्ति को चिकित्सा अधिकारी सहायक सिविल सर्जन से कम रैंक के चिकित्सा अधिकारी के समक्ष जांच के लिए पेश करने का निर्देश देना चाहिए;

(4) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी भी बात के बावजूद, मेट्रोपॉलिटन शहरों में सहायक पुलिस आयुक्त के रैंक से नीचे के किसी भी पुलिस अधिकारी और अन्य जगहों पर पुलिस उपाधीक्षक या समकक्ष रैंक के पुलिस अधिकारी को किसी की जांच 1987 के इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध नहीं करनी चाहिए।

इस अधिनियम के कठोर प्रावधानों को देखते हुए यह आवश्यक है। इससे भी अधिक तब जब भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17 के तहत और अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम, 1956 की धारा 13 के तहत, केवल एक निर्दिष्ट रैंक के पुलिस अधिकारी को उन निर्दिष्ट अधिनियमों के तहत अपराधों की जांच करने के लिए अधिकृत किया जाता है।

(5) पुलिस अधिकारी यदि न्यायिक हिरासत से पूर्व–अभियोग या पूर्व–परीक्षण पूछताछ के लिए किसी व्यक्ति की हिरासत की मांग कर रहा है, उसे न केवल इस तरह की हिरासत का कारण बताने के लिए बल्कि पुलिस हिरासत मांगने में देरी, यदि कोई हो, के लिए भी शपथ पत्र दाखिल करना होगा;

(6) यदि पूछताछ के लिए ले जाया गया व्यक्ति, वैधानिक चेतावनी प्राप्त होने पर कि वह स्वीकारोक्ति करने के लिए बाध्य नहीं है और यदि वह ऐसा करता है, तो उक्त बयान को उसके खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, अपने चुप्पी के अधिकार का दावा करता है, पुलिस अधिकारी को प्रकटीकरण का बयान देने के लिए कोई बाध्यता किए बिना दावे के अपने अधिकार का सम्मान करना चाहिए;

केंद्र सरकार इन दिशानिर्देशों पर ध्यान दे सकती है और उन्हें अधिनियम और नियमों में उचित संशोधन द्वारा शामिल कर सकती है।

1985 अधिनियम को 23 मई को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और 24 मई, 1985 को लागू हुआ। इस अधिनियम की प्रस्तावना में कहा गया है कि इस अधिनियम के विशेष प्रावधान "आतंकवादियों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए", विघटनकारी गतिविधियों और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए बनाए गए थे"।

(जोर दिया गया)

अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार है:–

"प्रीफेटरी नोट – उद्देश्यों और कारणों का विवरण। – आतंकवादी ज्यादातर पंजाब और चंडीगढ़ में बेतहाशा हत्याएं, आगजनी, संपत्तियों की लूटपाट और अन्य जघन्य अपराधों में लिप्त रहे हैं। 10 मई, 1985 के बाद से, आतंकवादियों ने अन्य हिस्सों में अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है देश के, यानी दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जिसके परिणामस्वरूप कई निर्दोष लोगों की जान चली गई और कई को गंभीर चोटें आईं। ट्रेनों, बसों और सार्वजनिक स्थानों पर विस्फोटक उपकरण लगाने, आतंक पैदा करने का उद्देश्य नागरिकों के मन में भय और दहशत और सांप्रदायिक शांति और सद्भाव को बाधित करना स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह आतंकवाद का एक नया और स्पष्ट चरण है, जिस पर गंभीरता से ध्यान देने और प्रभावी ढंग से और शीघ्रता से निपटने की आवश्यकता है। विघटनकारी (गतिविधियों) में चिंताजनक वृद्धि यह भी गंभीर चिंता का विषय है।"

चूँकि 1985 का अधिनियम 23 मई 1987 को समाप्त होने वाला था, राष्ट्रपति ने आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अध्यादेश, 1987 (1987 का 2) प्रख्यापित किया जो 24 मई 1987 से लागू हुआ। अध्यादेश को 1987 के अधिनियम (संख्या 28 सन् 1987) द्वारा निरस्त कर दिया गया जिसे 3.9.87 को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई। हालाँकि, 1985 के अधिनियम और

1987 के अधिनियम में विशेष प्रावधानों की योजना वही है। अधिनियम की योजना, आतंकवादियों की रोकथाम और विघटनकारी गतिविधियों और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों से निपटने के लिए है।

1987 के अधिनियम को 1993 के संशोधन अधिनियम 43 द्वारा और संशोधित किया गया था। संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों का विवरण इस प्रकार है: –

> "आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1985 देश के कई हिस्सों में बढ़ती आतंकवादी गतिविधियों की पृष्ठभूमि में 23 मई, 1985 को लागू किया गया था। यह अधिनियम 24 मई, 1985 से इस शर्त के साथ लागू हुआ कि यह इसके प्रारंभ होने की तारीख से दो साल की अवधि के लिए वैध रहेगा क्योंकि उस समय यह आशा की गई थी कि दो साल की अवधि में आतंकवाद के खतरे को नियंत्रित करना संभव होगा। दुर्भाग्य से, आतंकवादी हिंसा बेरोकटोक जारी है, जिससे सरकार को 1987, 1989 और 1991 में नियत तिथियों पर समय–समय पर अधिनियम का विस्तार करने की आवश्यकता हुई। अधिनियम का जीवन अब 23 मई, 1993 को समाप्त होने वाला है। इन विस्तारों पर कार्रवाई करते समय राज्य सरकारों के विचार प्राप्त किए गए थे और उनमें से अधिकांश ने अधिनियम के विस्तार की सिफारिश की थी।
>
> 2. आतंकवाद जो शुरू में पंजाब, जम्मू और कश्मीर और उत्तर पूर्व के राज्यों तक ही सीमित था, उसने अपना जाल उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और पश्चिम बंगाल राज्यों तक फैला लिया है। इसके अलावा, अत्याधुनिक हथियारों, रिमोट कंट्रोल उपकरणों, रॉकेट लॉन्चरों, पेशेवर प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी ने समस्या में एक नया और परेशान करने वाला आयाम जोड़ दिया है।
>
> 3. आतंकवाद का खतरा भी अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय रहा है। हाल ही में, हमने आतंकवादी अपराध की जांच और अभियोजन और अपराध और आतंकवादी फंडों की आय और उपकरणों का पता लगाने, संयम और जब्ती में पारस्परिक सहायता के लिए यूनाइटेड किंगडम के साथ एक समझौता किया है। यह समझौता विशेष रूप से विदेशों से प्रेरित आतंकवाद से निपटने में उपयोगी है।
>
> 4. उपरोक्त विचारों को ध्यान में रखते हुए, कुछ मौजूदा प्रावधानों को बढ़ाने का प्रस्ताव है ताकि आतंकवादियों के अपराध की जांच और अभियोजन में पारस्परिक सहायता के लिए

यूनाइटेड किंगडम के साथ हाल ही में हस्ताक्षरित समझौते को भी मूर्त रूप दिया जा सके और अपराध और आतंकवादी फंडों की आय और साधनों का पता लगाया जा सके, उन पर लगाम लगाई जा सके और उन्हें जब्त किया जा सके और अधिनियम को दो साल की अवधि के लिए 23 मई, 1995 तक बढाया जा सके।

5. वर्तमान विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।"

इस प्रकार, इस प्रकार के असाधारण कानून कठोर, कठोर और कड़े प्रावधान प्रदान करके, विशेष प्रक्रिया निर्धारित करके, सामान्य प्रक्रियात्मक कानून के तहत निर्धारित प्रक्रिया से हटकर असाधारण स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि प्रचलित सामान्य प्रक्रियात्मक कानून को पाया गया था। आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों में लिप्त अपराधियों से निपटने के लिए अपर्याप्त और पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं पाया गया था। जैसा कि ऊपर बताया गया है, उद्देश्यों और कारणों की प्रस्तावना और कथन स्पष्ट रूप से स्पष्ट हैं कि इस तरह का असाधारण अधिनियम आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों की रोकथाम और उनसे निपटने के लिए और उनसे जुड़े तत्संबंधी आकस्मिक मामलों के लिए असाधारण स्थिति से निपटने के लिए बनाया गया था। .

अधिनियम के तहत 'आतंकवाद'शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। हितेंद्र विष्णु ठाकुर बनाम महाराष्ट्र राज्य, [1994] 4 एससीसी 602 में इस न्यायालय ने पैराग्राफ 7 (एससीसी पृष्ठ 618) में निम्नानुसार व्यवस्था दी है:–..

"7. 'आतंकवाद'बढ़ती अराजकता और हिंसा के पंथ की अभिव्यक्तियों में से एक है। हिंसा और अपराध स्थापित व्यवस्था के लिए ख़तरा हैं और सभ्य समाज के ख़िलाफ़ विद्रोह हैं। "आतंकवाद'को टाडा के तहत परिभाषित नहीं किया गया है और न ही 'आतंकवाद'की सटीक परिभाषा देना या यह बताना संभव है कि 'आतंकवाद'क्या है। इसे हिंसा के उपयोग के रूप में वर्णित करना संभव हो सकता है जब इसका सबसे महत्वपूर्ण परिणाम केवल पीड़ित की शारीरिक और मानसिक क्षति लेकिन इसका पूरे समाज पर लंबे समय तक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है या उत्पन्न होने की संभावना होती है। इस प्रक्रिया में मृत्यु, चोट, या संपत्ति का विनाश या यहां तक कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन भी हो सकता है लेकिन इच्छित आतंकवादी गतिविधि की सीमा और पहुंच देश के सामान्य दंड कानून के तहत दंडित किए जाने योग्य एक सामान्य अपराध के प्रभाव से परे है और इसका मुख्य उद्देश्य सरकार को डराना या समाज के सद्भाव को बिगाड़ना या लोगों को ओर समाज को "आतंकित"करना है

और न केवल सीधे तौर पर उन पर हमला किया गया, बल्कि समाज की गति, शांति और स्थिरता को भी बाधित करने और भय और असुरक्षा की भावना पैदा करने के उद्देश्य से हमला किया गया। एक आतंकवादी'गतिविधि केवल कानून और व्यवस्था या सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा करने से उत्पन्न नहीं होती है। इच्छित गतिविधि का परिणाम ऐसा होना चाहिए कि यह सामान्य दंड कानून के तहत इससे निपटने के लिए सामान्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता से परे हो। अनुभव ने हमें दिखाया है कि 'आतंकवाद'आम तौर पर बड़े पैमाने पर या उसके किसी भी वर्ग के लोगों के मन में भय और असहायता पैदा करके सत्ता हासिल करने या नियंत्रण बनाए रखने का एक प्रयास है और यह पूरी तरह से असामान्य घटना है। इसलिए, जो बात 'आतंकवाद'को हिंसा के अन्य रूपों से अलग करती है, वह जबरदस्ती धमकी का जानबूझकर और व्यवस्थित उपयोग प्रतीत होता है। अधिकांशतः, आज एक कट्टर अपराधी स्थिति का लाभ उठाता है और 'आतंकवाद'का लबादा पहनकर समाज में अपने लिए स्वीकार्यता और सम्मान हासिल करना चाहता है क्योंकि दुर्भाग्य से उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में, एक 'आतंकवादी'को अपने समूह द्वारा और अक्सर गुमराह युवाओं द्वारा भी एक नायक के रूप में पेश किया जाता है। इसलिए, ऐसे अपराधी के साथ व्यवहार करना और उसके साथ देश के दंड कानून के तहत सामान्य अदालतों में मुकदमा चलाने में सक्षम एक सामान्य अपराधी से अलग व्यवहार करना आवश्यक है। भले ही एक 'आतंकवादी'और एक सामान्य अपराधी द्वारा किया गया अपराध एक हद तक ओवरलैप हो सकता है, लेकिन विधायिका का यह इरादा नहीं है कि हर अपराधी पर टाडा के तहत मुकदमा चलाया जाए, जहां उसकी गतिविधि का नतीजा सामान्य आपराधिक गतिविधि की सामान्य सीमाओ से आगे न बढ़े। प्रत्येक 'आतंकवादी'अपराधी हो सकता है लेकिन टाडा के अधिक कठोर प्रावधानों को लागू करने के लिए प्रत्येक अपराधी को 'आतंकवादी'का लेबल नहीं दिया जा सकता है। टाडा को लागू करने के लिए आपराधिक गतिविधि को अधिनियम की धारा 3(1) के अनुसार अपेक्षित इरादे से ऐसे हथियारों का उपयोग करके प्रतिबद्ध किया जाना चाहिए जैसा कि धारा 3(1) में बताया गया है और जो उक्त धारा में उल्लिखित अपराधो का कारण बनता है या होने की संभावना है।

जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, अधिनियम आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों की रोकथाम और उनसे निपटने और उनसे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के उद्देश्यों और कारणों के विवरण को प्राप्त करने के उद्देश्य से कठोर और कड़े प्रावधान प्रदान करता है।

कानून जितना सख्त होगा, न्यायालय की विचारशीलता उतनी ही कम होगी। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कड़े कानून बनाये जाते हैं। यह विधायिका का इरादा होने के नाते न्यायालय का कर्तव्य है कि वह यह देखे कि विधायिका का इरादा विफल न हो। यदि क़ानून में कोई संदेह या अस्पष्टता हो तो उद्देश्यपूर्ण निर्माण के नियम का सहारा उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए लेना चाहिए। (स्वीडिश मैच एबी और अन्य बनाम सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड, भारत और अन्य देखें, (2004) 7 स्केल 158 पैरा 84 पृष्ठ 176 पर)

आगे बढ़ने से पहले, हम इस स्तर पर इस विषय पर इस न्यायालय के कुछ निर्णयों पर ध्यान दे सकते हैं। बिलाल अहमद कालू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य [1997] 7 एससीसी 431 के मामले में, इस न्यायालय की दो–न्यायाधीश पीठ ने पैराग्राफ 5 (एससीसी पृष्ठ 434) में निम्नानुसार निर्णय दिया: –

> "5. जिन अपराधों के लिए अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया था, उनसे निपटते समय उसके द्वारा दिए गए इकबालिया बयान पर गौर करने का कोई सवाल ही नहीं है, उस पर भरोसा करना तो दूर की बात है क्योंकि उसे टाडा के तहत सभी अपराधों से बरी कर दिया गया था। किसी पुलिस अधिकारी को दिया गया कोई भी बयान इन अपराधों के लिए साक्ष्य में अस्वीकार्य है और इसलिए यह काफी हद तक माना जाता है कि दंड संहिता के तहत अपराधों के संबंध में उक्त प्रतिबंध केवल इसलिए समाप्त नहीं होगा क्योंकि मुकदमा टाडा के तहत अपराधों के लिए भी नामित न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया था। इसलिए मामला अन्य सबूतों के आधार पर उसके खिलाफ खड़ा होगा या गिर जाएगा।"

यह निर्णय 6 अगस्त, 1997 को दिया गया था। उसी दिन उसी पीठ द्वारा एक और निर्णय रामभाई नाथाभाई गढ़वी बनाम गुजरात राज्य, [1997] 7 एससीसी 744 के मामले में दिया गया था, जहां इसे पैराग्राफ 18 (एससीसी पृष्ठ 751) में निम्नानुसार बताया गया था:

> "18. यह स्पष्ट है कि टाडा अपराधों के अलावा किसी अन्य अपराध के लिए आरोपी पर आरोप लगाने की नामित अदालत की शक्ति का प्रयोग केवल टाडा के तहत किसी भी अपराध के लिए आयोजित मुकदमे में किया जा सकता है। जब धारा 20–ए(2) में परिकल्पित वैध मंजूरी के अभाव में टाडा के तहत अपराध के लिए नामित न्यायालय द्वारा मुकदमा आयोजित नहीं किया जा सकता था तो इसका परिणाम यह हुआ कि शस्त्र अधिनियम के तहत किसी भी अपराध में उस अदालत द्वारा कोई वैध मुकदमा नहीं चलाया

जा सकता। यह स्पष्ट है कि एक नामित न्यायालय के पास कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है किसी अन्य अपराध की कोशिश करने के लिए। इसलिए, वर्तमान मामले में नामित न्यायालय द्वारा एकत्र की गई सामग्री पर शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत कोई दोषसिद्धि संभव नहीं है।"

यह ध्यान दिया जाएगा कि दोनों निर्णयों में अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों पर ध्यान नहीं दिया गया है। बिलाल अहमद के मामले में दिए गए निर्णय का गुरप्रीत सिंह बनाम पंजाब राज्य, [2002] 10 एससीसी 201 में पालन किया गया।

बिलाल अहमद के मामले में दिए गए निर्णय को राज्य बनाम नलिनी, [1999] 5 एससीसी 253 मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने देखा। नलिनी के मामले में बेंच ने बिलाल अहमद के मामले में फैसले पर पुनर्विचार किया और बिलाल अहमद के मामले में फैसले को खारिज कर दिया। हालाँकि, रुंभुल के मामले और गुरप्रीत सिंह के मामले के फैसलों पर नलिनी के मामले में ध्यान नहीं दिया गया है। नोलिनी के मामले में फैसले के मद्देनजर रामबाही और गुरप्रीत सिंह के मामले में दो जजों की बेंच द्वारा दिया गया फैसला गलत है।

निर्धारण के लिए इस पीठ को भेजा गया प्राथमिक प्रश्न यह है कि क्या टाडा की धारा 15 के तहत विधिवत दर्ज किया गया इकबालिया बयान किसी अन्य कानून के तहत उन अपराधों के लिए स्वीकार्य रहेगा, जिनकी सुनवाई अधिनियम की धारा 12 के तहत टाडा अपराधों के साथ की गई थी, इस तथ्य के बावजूद कि उक्त मुकदमे में आरोपी को टाडा के तहत अपराधों से बरी कर दिया गया था।

समाप्ति के लिए हमारे सामने जो प्रश्न रखे गए हैं, वे अब समग्र नहीं रह गए हैं। हमारे विचार में, नलिनी (उपरोक्त) में दिए गए तीन–न्यायाधीशों की बेंच के फैसले से इसे आराम मिल गया है। नलिनी के मामले में धारा 12 और 15 की कठोरता पर विचार किया गया और पैराग्राफ 80, 81 और 82 (एससीसी पृष्ठ 304) में निष्कर्ष निम्नानुसार प्रस्तुत किया गया: –

"80. टाडा की धारा 12 निर्दिष्ट न्यायालय को आपराधिक प्रक्रिया संहिता के अनुसार टाडा के तहत किसी भी अपराध के साथ–साथ किसी भी अन्य अपराध "जिसके लिए आरोपी पर आरोप लगाया जा सकता है"की संयुक्त रूप से सुनवाई करने में सक्षम बनाती है। उप–धारा (2) यह नामित न्यायालय को ऐसे मुकदमे में अभियुक्त को "किसी अन्य कानून के तहत"किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराने का अधिकार देता है, यदि ऐसे मुकदमे में नामित न्यायालय द्वारा यह पाया जाता है कि अभियुक्त को ऐसे अपराध का दोषी पाया गया

है। यदि अभियुक्त ऐसे मुकदमे में टाडा के तहत अपराध से बरी कर दिया जाता है, लेकिन किसी अन्य कानून के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि किसी अन्य कानून के तहत ऐसे अन्य अपराध के लिए ही मुकदमा था।

81. टाडा की धारा 15 किसी अभियुक्त द्वारा उसमें निर्दिष्ट पुलिस अधिकारी को दिए गए इकबालिया बयान को "ऐसे व्यक्ति के मुकदमे में"स्वीकार्य बनाने में सक्षम बनाती है। इसका मतलब है, अगर टाडा के तहत किसी भी अपराध का मुकदमा किसी अन्य कानून के तहत किसी अन्य अपराध के साथ चल रहा था, तो इकबालिया बयान की स्वीकार्यता तब भी कायम रहेगी, भले ही आरोपी टाडा अपराधों के तहत बरी कर दिया गया हो।"

(जोर दिया गया)

82. धारा 12 की तुलना में धारा 15 के उपरोक्त निहितार्थ बिलाल अहमद मामले में टाडा को बढ़ावा नहीं दिया गया है। इसलिए उसमें टिप्पणियाँ (एससीसी पृष्ठ 434, पैरा 5 पर) कि

"जिन अपराधों के लिए अपीलकर्ता को दोषी ठहराया गया था, उनसे निपटने के दौरान उसके द्वारा दिए गए इकबालिया बयान पर गौर करने का कोई सवाल ही नहीं है, उस पर भरोसा करना तो दूर की बात है क्योंकि उसे टाडा के तहत सभी अपराधों से बरी कर दिया गया था।"

हमारे द्वारा अनुसरण नहीं किया जा सकता। सही स्थिति यह है कि टाडा की धारा 15 के तहत विधिवत दर्ज किया गया इकबालिया बयान किसी अन्य कानून के तहत अन्य अपराधों की तरह ही स्वीकार्य बना रहेगा, जिनकी सुनवाई टाडा अपराधों के साथ ही की गई थी, इससे कोई फर्क नहीं पडता कि आरोपी को उस मुकदमे में टाडा के तहत अपराध से बरी कर दिया गया था।"

(जोर दिया गया)

हम नलिनी के मामले में तीन–न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से सम्मानजनक सहमत हैं।

एस.एस.एम. कादरी न्यायाधिपति, ने अपने सहमति निर्णय में एससीसी पृष्ठ 571 के पैराग्राफ 674 और 675 में निम्नानुसार निर्णय लिया:–

"674. टाडा अधिनियम की धारा 12 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, धारा 15 के तहत दर्ज की गई स्वीकारोक्ति टाडा अधिनियम या नियमों के तहत अपराध के लिए किसी व्यक्ति, सह–अभियुक्त, उकसाने वाले या साजिशकर्ता के मुकदमे में स्वीकार्य होगी या इसके तहत बनाया गया और ऐसा अन्य अपराध जिसके लिए ऐसे व्यक्ति पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत एक ही मुकदमे में आरोप लगाया जा सकता है, बशर्ते टाडा अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत अपराध ऐसे अन्य अपराध से जुड़ा हो।

675. उपधारा (1) धारा 15 के विश्लेषण से पता चलता है कि इसके दो अंग हैं। पहला अंग आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों को किसी ऐसे पुलिस अधिकारी के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा की गई स्वीकारोक्ति पर लागू होने से रोकता है जो पुलिस अधीक्षक से कम रैंक का न हो और उसके द्वारा धारा में उल्लिखित किसी भी तरीके से दर्ज किया गया हो। दूसरा अंग ऐसी स्वीकारोक्ति को स्वीकार्य बनाता है, टाडा अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत अपराध के लिए ऐसे व्यक्ति या सह–अभियुक्त, उकसाने वाले या साजिशकर्ता के मुकदमे में साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, बशर्ते कि सह–अभियुक्त, उकसाने वाला या साजिशकर्ता आरोपी के साथ एक ही मामले में आरोप लगाया गया और मुकदमा चलाया गया। धारा 15 (1) का तात्पर्य यह है कि जहां तक सीआरपीसी के प्रावधानों और साक्ष्य अधिनियम में उल्लिखित रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति की स्वीकारोक्ति की रिकॉर्डिंग के साथ टकराव होता है,धारा में निर्दिष्ट किसी भी तरीके से, या परीक्षण में इसकी स्वीकार्यता के लिए, उन्हें टाडा अधिनियम की धारा 15 (1) के प्रावधान के अनुसार झुकना होगा, जैसा कि अधिभावी प्रभाव दिया गया है।"

एससीसी पेज 580 के पैराग्राफ 704 में यह भी बताया गया था कि टाडा अधिनियम की धारा 15 के तहत एक आरोपी का कबूलनामा आरोपी के साथ संयुक्त रूप से मुकदमा चलाने वाले सह–अभियुक्त, दुष्प्रेरक या साजिशकर्ता के खिलाफ ठोस सबूत है।

इससे पहले कि हम धारा 15 और 12 की कठोरता पर विचार करें, हम इस स्तर पर बता सकते हैं कि यह एक घिसा–पिटा कानून है कि किसी क़ानून की व्याख्या करने के लिए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को केवल अस्पष्टता के मामले में ही लागू किया जा सकता है। जब क़ानून की भाषा स्पष्ट और स्पष्ट हो तो न्यायालय कानून या इरादे का दायरा नहीं बढ़ा सकता। संकीर्ण और पांडित्यपूर्ण गठन को हमेशा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। अदालतों को ऐसे गठन से बचना चाहिए जो कानून को

निरर्थक बना देगा। यह भी अच्छी तरह से स्थापित है कि प्रत्येक क़ानून की उसकी भाषा में किसी भी प्रकार की हिंसा किए बिना व्याख्या की जानी चाहिए। यह भी सामान्य बात है कि जब कोई अभिव्यक्ति एक से अधिक अर्थ देने में सक्षम होती है, तो अदालत वैकल्पिक निर्माण के परिणामों को ध्यान में रखते हुए, प्रावधान के उद्देश्य के अनुरूप अस्पष्टता को हल करने का प्रयास करेगी। इस संबंध में, हम इस न्यायालय के कुछ निर्णयों पर ध्यान दे सकते हैं।

नसीरुद्दीन बनाम सीता राम अग्रवाल, [2003] 2 एससीसी 577 में, इस न्यायालय के तीन न्यायाधीश–पीठ ने पैराग्राफ 35 और 37 (एससीसी पृष्ठ 588) और (एससीसी पृष्ठ 589) में निम्नानुसार बताया: –

> "35. ऐसे मामले में जहां वैधानिक प्रावधान स्पष्ट और स्पष्ट है, अदालत केवल उससे उत्पन्न होने वाले कठोर परिणामों के कारण अलग तरीके से उसकी व्याख्या नहीं करेगी।"
>
> "37. किसी मूर्ति की व्याख्या करने के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग तब किया जा सकता है जब वह अस्पष्ट हो। यह सर्वविदित है कि किसी दिए गए मामले में अदालत कपड़े को इस्त्री कर सकती है लेकिन वह कपड़े की बनावट को नहीं बदल सकती है। वह दायरे को बड़ा नहीं कर सकती है कानून या इरादे का जब प्रावधान की भाषा सीधी और स्पष्ट है। यह किसी प्रतिमा में शब्दों को जोड़ या घटा नहीं सकता है या उसमें कुछ ऐसा नहीं पढ़ सकता है जो वहां नहीं है। यह कानून को फिर से लिख या पुनर्निर्मित नहीं कर सकता है। यह निर्धारित करना भी आवश्यक है कि वहां एक धारणा मौजूद है कि विधायिका ने किसी भी अनावश्यक शब्दों का उपयोग नहीं किया है। यह अच्छी तरह से तय है कि इस्तेमाल की गई भाषा से कानून का वास्तविक इरादा पता चल जाना चाहिए। यह सच हो सकता है कि "होगा या हो सकता है"अभिव्यक्ति का उपयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए निर्णायक नहीं है कि कानून निर्देशक और अनिवार्य है या नहीं। लेकिन विधायिका की मंशा का पता अधिनियम की योजना से लगाया जाना चाहिए। यह भी समान रूप से अच्छी तरह से स्थापित है कि जब नकारात्मक शब्दों का उपयोग किया जाता है तो अदालतें यह मान लेंगी कि विधायिका का इरादा यह था कि प्रावधान अनिवार्य हैं।"

(मोहन कुमार सिंघानिया बनाम भारत संघ, [1992] पूरक 1 एससीसी 594 (एससीसी पृष्ठ 624) पैरा 67 भी देखें।

बलराम कुमावत बनाम भारत संघ, [2003] 7 एससीसी 628 के मामले में, इस न्यायालय की तीन–न्यायाधीशों की पीठ ने एससीसी पेज 635 के पैराग्राफ 23 में निम्नानुसार बताया:–

> "इसके अलावा, दंडात्मक क़ानून के संबंध में भी किसी भी संकीर्ण और पांडित्यपूर्ण, शाब्दिक और शाब्दिक व्याख्या को हमेशा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। कानून की व्याख्या अपराध की विषय–वस्तु और कानून के उद्देश्य को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए और कानून का उद्देश्य यह हासिल करना चाहता है। कानून का उद्देश्य अपराधी को जाल से छिपकर बाहर निकलने की अनुमति देना नहीं है। आपराधिक न्यायशास्त्र ऐसा नहीं कहता.

और आगे एससीसी पृष्ठ 638 के पैराग्राफ 30 में इसे इस प्रकार बताया गया है: –

> "30.एक बार फिर सुपरिंटेंडेंट एंड रिमेंबरेंसर ऑफ लीगल अफेयर्स टू गवर्नमेंट ऑफ डब्ल्यू.बी. बनाम अबानी मैती [1979] 4 एससीसी 85 में कानून निम्नलिखित शब्दों में कहा गया है: (एससीसी पृष्ठ 90, पैरा 18)
>
> > "19(18).एक्सपोज़िशन एक्स विसेरिबस एक्टस व्याख्या का एक लंबे समय से मान्यता प्राप्त नियम है। एक मूर्ति में शब्द अक्सर समग्र रूप से क़ानून के संदर्भ से अपना अर्थ लेते हैं। इसलिए, उन्हें अलग से नहीं समझा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, 'हो सकता है'शब्द का उपयोग आम तौर पर यह संकेत देगा कि प्रावधान अनिवार्य नहीं था। लेकिन किसी विशेष क़ानून के संदर्भ में, यह शब्द एक विधायी अनिवार्यता का संकेत दे सकता है, खासकर तब जब एक अनुमेय अर्थ में इसकी व्याख्या इसे अविश्वसनीय बना देगी,जैसे कि यहएक प्रभावशाली देवदूत की तरह है, जो व्यर्थ में एक चमकदार शून्य में अपने पंख फड़फड़ा रहा है।"विस्काउंट साइमन, एल.सी. ने नोक्स बनाम डोनकास्टर अमलगमेटेड कोलियरीज, लिमिटेड में कहा है कि यदि विकल्प दो व्याख्याओं के बीच है', तो – (एसी पृष्ठ 1022 पर)
>
> 'जिनमें से ज्यादा संकीर्ण कानून के स्पष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल होगी, हमें ऐसे निर्माण से बचना चाहिए जो कानून को निरर्थकता में बदल देगा और इस दृष्टिकोण के आधार पर अधिक साहसी निर्माण को स्वीकार करना चाहिए कि संसद केवल प्रभावी परिणाम लाने के उद्देश्य से कानून बनाएगी।

संदर्भित निर्णयों की पृष्ठभूमि में और अधिनियम की विधायी मंशा और योजना को ध्यान में रखते हुए, अब हम अधिनियम की धारा 15 और 12 की कठोरता की जांच कर सकते हैं।

धारा 15 पुलिस अधिकारियों को दिए गए कुछ बयानों पर विचार करने से संबंधित है। यह पढ़ता है:–

> (1) संहिता या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) में किसी बात के होते हुए भी, लेकिन इस धारा के प्रावधानों के अधीन, पुलिस अधीक्षक से कम रैंक के पुलिस अधिकारी के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा की गई स्वीकारोक्ति और ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा लिखित रूप में या कैसेट, टेप या ध्वनि ट्रैक जैसे किसी यांत्रिक उपकरण पर रिकॉर्ड किया गया है जिसमें से ध्वनि या छवियों को पुन: प्रस्तुत किया जा सकता है, ऐसे व्यक्ति (या सह–आरोपी, दुष्प्रेरक या साजिशकर्ता) के मुकदमे में इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी अपराध के लिए स्वीकार्य होगा:

बशर्ते कि सह–अभियुक्त, दुष्प्रेरक या षडयंत्रकर्ता पर आरोपी के साथ एक ही मामले में आरोप लगाया जाए और मुकदमा चलाया जाए।

> (2) पुलिस अधिकारी, उप–धारा (1) के तहत किसी भी बयान को दर्ज करने से पहले, इसे करने वाले व्यक्ति को समझाएगा कि वह बयान देने के लिए बाध्य नहीं है और यदि वह ऐसा करता है, तो इसे सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है वह और ऐसा पुलिस अधिकारी ऐसी किसी भी स्वीकारोक्ति को तब तक रिकॉर्ड नहीं करेंगे जब तक कि ऐसा करने वाले व्यक्ति से पूछताछ करने पर उसके पास यह विश्वास करने का कारण न हो कि यह स्वेच्छा से किया जा रहा है।

नियम 15 पुलिस अधिकारियों को दिए गए इकबालिया बयान की रिकॉर्डिंग से संबंधित है। यह पढ़ता है:–

> (1) किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा किया गया इकबालिया बयान और ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 15 के तहत दर्ज किया गया बयान हमेशा उसी भाषा में दर्ज किया जाएगा जिसमें ऐसा कबूलनामा किया गया है और यदि वह व्यावहारिक नहीं है, तो ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा आधिकारिक उद्देश्यों के लिए या निर्दिष्ट न्यायालय की भाषा में उपयोग की जाने वाली भाषा में और यह रिकॉर्ड का हिस्सा बनेगा।
>
> (2) इस प्रकार दर्ज की गई स्वीकारोक्ति को संबंधित व्यक्ति को दिखाया, पढ़ा या सुनाया जाएगा और यदि वह भाषा नहीं समझता है, जो दर्ज किया गया है, उसकी व्याख्या उसे उस

भाषा में की जाएगी जिसे वह समझता है और वह अपनी स्वीकारोक्ति को समझाने या उसमें कुछ जोड़ने के लिए स्वतंत्र होगा।

(3) स्वीकारोक्ति, यदि यह लिखित में है, तो वह

(ए) स्वीकारोक्ति करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगी; और

(बी) पुलिस अधिकारी द्वारा जो अपने हाथ से यह भी प्रमाणित करेगा कि ऐसी स्वीकारोक्ति उसकी उपस्थिति में ली गई थी और उसके द्वारा दर्ज की गई थी और रिकॉर्ड में उस व्यक्ति द्वारा की गई स्वीकारोक्ति का पूर्ण और सच्चा विवरण शामिल है और ऐसा पुलिस अधिकारी स्वीकारोक्ति के अंत में निम्नलिखित आशय का एक ज्ञापन करेगा :–

"मैंने (नाम) को समझाया है कि वह स्वीकारोक्ति करने के लिए बाध्य नहीं है और यदि वह ऐसा करता है, तो उसके द्वारा किया गया कोई भी बयान उसके खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और मेरा मानना है कि यह बयान स्वेच्छा से दिया गया था। इसे लिया गया था मेरी उपस्थिति और सुनवाई में और मेरे द्वारा रिकॉर्ड किया गया और इसे बनाने वाले व्यक्ति को पढ़ा गया और उसके द्वारा इसे सही माना गया, और इसमें उसके द्वारा किए गए बकवास का पूरा और सच्चा विवरण शामिल है।

हस्ताक्षर /– पुलिस अधिकारी."

(4) जहां इकबालिया बयान किसी यांत्रिक उपकरण पर दर्ज किया गया है, वहां तक उप–नियम (3) में निर्दिष्ट ज्ञापन जहां तक लागू है और बयान देने वाले व्यक्ति द्वारा की गई घोषणा है कि उक्त बयान यांत्रिक उपकरण पर दर्ज किया गया है उसकी उपस्थिति में सही ढंग से दर्ज किया गया है, स्वीकारोक्ति के अंत में यांत्रिक उपकरण में भी दर्ज किया जाएगा।

(5) उक्त धारा 15 के तहत दर्ज की गई प्रत्येक स्वीकारोक्ति को तुरंत मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा, जिसका उस क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र है जिसमें ऐसी स्वीकारोक्ति दर्ज की गई है और ऐसा मजिस्ट्रेट प्राप्त की गई स्वीकारोक्ति को दर्ज कर नामित न्यायालय को अग्रेषित करेगा जो अपराध का संज्ञान ले सकता है।

धारा 12 अन्य अपराधों के संबंध में नामित न्यायालयों की शक्ति से संबंधित है। यह पढ़ता है

(1) किसी अपराध का मुकदमा चलाते समय, एक नामित न्यायालय किसी अन्य अपराध का भी मुकदमा चला सकता है जिसके लिए संहिता के तहत आरोपी पर उसी मुकदमे में आरोप लगाया जा सकता है यदि अपराध ऐसे अन्य अपराधों से जुड़ा हुआ है।

(जोर दिया गया)

(2) यदि, इस अधिनियम के तहत किसी अपराध के मुकदमे के दौरान, यह पाया जाता है कि आरोपी व्यक्ति ने इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए किसी नियम या किसी अन्य कानून के तहत कोई अन्य अपराध किया है, तो नामित न्यायालय ऐसे व्यक्ति को दोषी ठहरा सकता है। ऐसे अन्य अपराध का व्यक्ति और उसकी सजा के लिए इस अधिनियम या ऐसे नियम या, जैसा भी मामला हो, ऐसे अन्य कानूनों द्वारा अधिकृत कोई भी सजा पारित कर सकता है।

दोनों अनुभागों को सरसरी तौर पर पढ़ने पर, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें प्रयुक्त भाषा स्पष्ट और स्पष्ट है। जैसा कि इस न्यायालय ने नलिनी के मामले में बताया (उपरोक्त) धारा 15 में दो अंग हैं। पहला अंग आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों को किसी ऐसे पुलिस अधिकारी के समक्ष किसी व्यक्ति द्वारा की गई स्वीकारोक्ति पर लागू होने से रोकता है जो पुलिस अधीक्षक से कम रैंक का न हो और उसके द्वारा धारा में उल्लिखित किसी भी तरीके से दर्ज किया गया दूसरा अंग ऐसी स्वीकारोक्ति को स्वीकार्य बनाता है तथा जो साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत टाडा अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत अपराध के लिए ऐसे व्यक्ति या सह–अभियुक्त, उकसाने वाले या साजिशकर्ता के जो साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, बशर्ते कि सह–अभियुक्त, उकसाने वाला या साजिशकर्ता अधिनियम की धारा 12 में दिए गए प्रावधान के अनुसार आरोपी के साथ एक ही मामले में आरोप लगाने और मुकदमा चलाये जाने हेतु उपबंधित करता है। यह भी बताया गया कि घटना में सी.आर.पी.सी. और साक्ष्य अधिनियम, धारा में निर्दिष्ट किसी भी तरीके से, उसमें उल्लिखित रैंक के एक पुलिस अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति की स्वीकारोक्ति की रिकॉर्डिंग, या परीक्षण में इसकी स्वीकार्यता के साथ टकराव में आता है, टाडा अधिनियम की धारा 15 का सीआर.पी.सी. और साक्ष्य अधिनियम पर अत्यधिक प्रभाव पडेगा।

अपीलकर्ताओं के वकील ने दृढ़तापूर्वक आग्रह किया कि धारा 15 में प्रयुक्त शब्द "इस अधिनियम के तहत अपराध के लिए"सुझाव देते हैं कि धारा 15 के तहत प्रदान किए गए तरीके से दर्ज की गई स्वीकारोक्ति यदि टाडा के तहत कोई अपराध नहीं बनता है, साक्ष्य में स्वीकार्य स्वीकारोक्ति को बाहर कर देती है। दूसरे शब्दों में, धारा 15 के तहत दिए गए तरीके से दर्ज की गई स्वीकारोक्ति में अन्य अपराधों के संबंध में साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य स्वीकारोक्ति शामिल नहीं है। वकील ने यह भी आग्रह किया कि शब्द, "लेकिन इस धारा के प्रावधानों के अधीन"यह भी सुझाव देते हैं कि उक्त प्रावधान केवल टाडा अपराधों तक ही सीमित हैं। हम इस विवाद को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। टाडा अधिनियम की धारा 15 और उसके तहत बनाए गए नियम अपने आप में एक स्व–निहित संहिता है, जो प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय प्रदान करता है और इसमें प्रयुक्त शब्दों "लेकिन इस धारा के प्रावधानों के अधीन"का अर्थ धारा के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय होगा। जैसा कि पहले ही बताया गया है कि धारा 15 का साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता पर अधिभावी प्रभाव है, स्वीकारोक्ति दर्ज करने में पालन की जाने वाली एकमात्र प्रक्रिया धारा 15 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत निर्धारित प्रक्रिया है। धारा 15(1) में "लेकिन इस धारा के प्रावधानों के अधीन"शब्दों को शामिल करते समय विधान का यही एकमात्र उद्देश्य होगा।

जहां तक "इस अधिनियम के तहत अपराध के लिए"शब्दों का संबंध है, धारा 15(1) में संदर्भित 'अधिनियम'शब्द अधिनियम की धारा 12 से संबंधित है। इसलिए धारा 15 को धारा 12 के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

अब तक यह कानून का अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि किसी क़ानून का कोई भी हिस्सा और क़ानून का कोई भी शब्द अलग–अलग नहीं समझा जा सकता है। क़ानूनों की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए कि हर शब्द का अपना स्थान हो और हर चीज़ अपनी जगह पर हो। यह भी सामान्य बात है कि उसके तहत बनाए गए क़ानून या नियमों को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और एक प्रावधान को दूसरे प्रावधान के संदर्भ में समझा जाना चाहिए ताकि प्रावधान को प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के अनुरूप बनाया जा सके।

भारतीय रिज़र्व बैंक बनाम पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड, [1987] 1 एससीसी 424 में, इस न्यायालय ने कहा: (एससीसी पृष्ठ 450, पैरा 33)

> "33. व्याख्या को पाठ और संदर्भ पर निर्भर होना चाहिए। वे व्याख्या का आधार हैं। कोई यह कह सकता है कि यदि पाठ बनावट है, तो संदर्भ वह है जो रंग देता है। किसी को भी

> नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दोनों महत्वपूर्ण हैं। वह व्याख्या सबसे अच्छी है जो पाठ्य व्याख्या को प्रासंगिक से मेल कराती है। एक क़ानून की सबसे अच्छी व्याख्या तब होती है जब हम जानते हैं कि इसे क्यों अधिनियमित किया गया था। इस ज्ञान के साथ, क़ानून को पहले समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और फिर खंड दर खंड, खंड दर खंड, वाक्यांश दर वाक्यांश और शब्द दर शब्द पढ़ा जाना चाहिए। यदि किसी क़ानून को उसके अधिनियमन के संदर्भ में, क़ानून–निर्माता के चश्मे से देखा जाता है, तो ऐसे संदर्भ द्वारा प्रदान की गई, इसकी योजना, अनुभाग, खंड, वाक्यांश और शब्द रंग ले सकते हैं, इसके बजाय जब क़ानून को संदर्भ द्वारा प्रदान किए गए चश्मे के बिना देखा जाता है, तो अलग–अलग दिखाई दे सकते हैं। इन चश्मे से हमें अधिनियम को समग्र रूप से देखना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि प्रत्येक अनुभाग, प्रत्येक खंड, प्रत्येक वाक्यांश और प्रत्येक शब्द का क्या मतलब है और यह कहने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि यह संपूर्ण अधिनियम की योजना में फिट बैठता है। किसी क़ानून के किसी भी भाग और किसी क़ानून के किसी भी शब्द को अलग करके नहीं समझा जा सकता। क़ानूनों की व्याख्या इस प्रकार की जानी चाहिए कि हर शब्द का अपना स्थान हो और हर चीज़ उसमें जगह पर हो।"
>
> (जोर दिया गया)

अनवर हसन खान बनाम मोहम्मद शाफ़्ट एवं अन्य में [2001] 8 एससीसी 540, इस न्यायालय ने कहा:

> 8. किसी क़ानून के निर्माण का यह प्रमुख सिद्धांत है कि इसके प्रावधानों को बनाने में संघर्ष से बचकर और सामंजस्यपूर्ण निर्माण को अपनाकर प्रयास किया जाना चाहिए। उसके तहत बनाए गए क़ानून या नियमों को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और एक प्रावधान को दूसरे प्रावधान के संदर्भ में समझा जाना चाहिए ताकि प्रावधान को प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के अनुरूप बनाया जा सके.....

धारा 12 जो नामित न्यायालय को किसी अन्य अपराध की सुनवाई करने का अधिकार देती है जिसके लिए आरोपी पर उसी मुकदमे में संहिता के तहत आरोप लगाया जा सकता है, बशर्ते कि अपराध ऐसे अन्य अपराध से जुड़ा हो। इस धारा को अधिनियम की प्रस्तावना के अनुरूप क़ानून की किताब में लाया गया है, जो कहती है, "आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों की रोकथाम और

उनसे निपटने के लिए और उनसे जुड़े या प्रासंगिक मामलों के लिए।"इसलिए, आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े या उनके आनुषंगिक मामलों की देखभाल के लिए धारा 12 पेश की गई है।

समग्र रूप से दो खंडों का एक संयुक्त पाठन, कोई संदेह नहीं छोड़ती है कि एक प्रावधान को दूसरे प्रावधान के संदर्भ में समझा जाना चाहिए और इसके विपरीत क्रम में ताकि प्रावधान को प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के अनुरूप बनाया जा सके। अधिनियम की योजना और उद्देश्य किसी व्यक्ति या सह–अभियुक्त, दुष्प्रेरक या षडयंत्रकारी के मुकदमे में अधिनियम की धारा 15 के तहत दर्ज की गई स्वीकारोक्ति की स्वीकार्यता है, जिस पर आरोपी के साथ एक ही मामले में आरोप लगाया जाता है और मुकदमा चलाया जाता है, जैसा कि अधिनियम की धारा 12 द्वारा बताया गया है।

वकील का तर्क है कि धारा 12 केवल टाडा के तहत अपराधों के साथ–साथ किसी अन्य कानून के तहत किए गए अपराधों के लिए नामित न्यायालय को मुकदमा चलाने और दोषी ठहराने का अधिकार देने वाला प्रावधान है, ताकि मुकदमे की बहुलता से बचा जा सके और नामित न्यायालय को प्रयास करने और दोषी ठहराने का अधिकार नहीं दिया गया है। अन्य अपराधों के लिए दोषी ठहराया जाए, भले ही टाडा के तहत अपराध न किया गया हो। क्या इसका मतलब यह है, "तुम्हारे दांत तो होंगे, लेकिन काटोगे नहीं"? हमें यह नहीं लगता। जब अदालतों के पास मुकदमा चलाने की शक्ति है, तो इसमें यह अंतर्निहित है कि उनके पास दोषी ठहराने की भी शक्ति है। वर्तमान मामले में धारा 12 की उप–धारा 2 स्पष्ट रूप से नामित न्यायालय को आरोपी व्यक्ति को ऐसे अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराने और अधिनियम द्वारा अधिकृत कोई भी सजा पारित करने का अधिकार देती है यदि अपराध ऐसे अन्य अपराध से जुड़ा है और यदि यह पाया जाता है कि आरोपी व्यक्ति ने कोई अन्य अपराध किया है।

जैसा कि ऊपर उद्धृत किया गया है, धारा 12 नामित अदालत को टाडा के तहत अपराधों के साथ–साथ किसी अन्य अपराध की सुनवाई करने के लिए अधिकृत करती है, जिसके लिए आरोपी पर उसी मुकदमे में सीआरपीसी के तहत आरोप लगाया जा सकता है। शक्ति के प्रयोग पर लगाया गया एकमात्र प्रतिबंध यह है कि टाडा के तहत अपराध किसी भी अन्य अपराध के साथ जुड़ा हुआ है जिसकी सुनवाई एक साथ की जा रही है। इसके अलावा, धारा 12(2) में प्रावधान है कि नामित न्यायालय आरोपी व्यक्ति को उस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए किसी नियम या किसी अन्य कानून के तहत अपराध के लिए दोषी ठहरा सकता है और उस अधिनियम या नियमों या किसी अन्य कानून के तहत अधिकृत कोई भी सजा पारित कर सकता है। यदि टाडा के तहत किसी मुकदमे के दौरान

आरोपी व्यक्तियों को उस अधिनियम या किसी नियम या किसी अन्य कानून के तहत कोई अपराध करते हुए पाया जाता है, मामला उसके लिए सज़ा का हो सकता है।

धारा 12(1) और (2) में अंतर्निहित विधायी मंशा स्पष्ट रूप से समझ में आती है, नामित न्यायालय को अधिनियम के तहत किए गए अपराधों के साथ–साथ किसी अन्य कानून के तहत किए गए अपराधों के लिए अभियुक्तों पर मुकदमा चलाने और उन्हें दोषी ठहराने का अधिकार देना, यदि अपराध अन्य अपराध से जुड़ा हुआ है। अधिनियम की धारा 12(1) में प्रयुक्त भाषा, "यदि अपराध ऐसे अन्य अपराध से जुड़ा है"का बहुत महत्व है। आवश्यक परिणाम यह है कि एक बार जब अन्य अपराध टाडा के तहत अपराध से जुड़ा होता है और यदि अभियुक्त पर संहिता के तहत आरोप लगाया जाता है और एक ही मुकदमे में एक साथ मुकदमा चलाया जाता है, तो नामित न्यायालय को किसी अन्य कानून के तहत अपराध के लिए अभियुक्त को दोषी ठहराने का अधिकार है, इस तथ्य के बावजूद कि टाडा के तहत कोई भी अपराध नहीं बनता है। विधायिका का यही एकमात्र उद्देश्य हो सकता है। अन्यथा मानने का मतलब होगा कानून को दोबारा लिखना या उसमें कुछ ऐसा पढ़ना जो वहां नहीं है।

वकील ने यह भी आग्रह किया कि धारा 12 की कठोरता भेदभावपूर्ण है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के क्रोध को आकर्षित करती है क्योंकि यह नामित न्यायालय को किसी अन्य कानून के तहत किए गए अपराधों के साथ–साथ आरोपियों को दोषी ठहराने का अधिकार देती है। टाडा इस प्रकार सामान्य कानून के तहत अभियुक्तों को उपलब्ध अधिकारों से वंचित कर देता है। हमारी राय में, यह विवाद ग़लत है। यह घिसा–पिटा कानून है कि अनुच्छेद 14 भेदभाव पर रोक लगाता है, लेकिन प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ संबंध रखते हुए, समझदार अंतर के आधार पर उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है। धारा 12 को लागू करने से जो उद्देश्य प्राप्त करने का प्रयास किया गया है वह आतंकवादी गतिविधियों से जुड़े या उनके लिए प्रासंगिक अपराध से निपटना है। दूसरा अपराध आतंकवादी अधिनियम के साथ जुड़ा हुआ और अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। जैसा कि करतार सिंह (उपरोक्त) में पहले ही बताया गया है कि टाडा के तहत मुकदमा सामान्य कानून से अलग है। जिन व्यक्तियों पर टाडा के प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाता है, वे व्यक्तियों का एक अलग वर्ग हैं और अपराध की गंभीर और क्रोधित प्रकृति के लिए उन पर मुकदमा चलाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया सामान्य अपराधियों और प्रक्रियाओं से भिन्न वर्गीकरण के अंतर्गत हैं। टाडा के तहत अभियुक्तों के समूहीकरण और विचारणीय अपराधों का यह भेद और

वर्गीकरण अधिनियम के सार्थक उद्देश्य और वस्तु को प्राप्त करने के लिए है, जैसा कि प्रस्तावना के साथ–साथ वस्तुओं और कारणों के कथन से परिलक्षित होता है।

अधिनियम, जैसा कि ऊपर देखा गया है, विशेष प्रयोजन के लिए एक विशेष प्रावधान है। यह सामान्य प्रक्रियात्मक कानून से हटकर है। सामान्य प्रक्रियात्मक कानून की उपलब्धता के अभाव में भेदभावपूर्ण व्यवहार की दलील उपलब्ध नहीं होगी।

उपरोक्त कारणों से, हमारा विचार है कि नलिनी के मामले में निर्णय ने सही कानून निर्धारित किया है और हमारा मानना है कि टाडा की धारा 15 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत विधिवत दर्ज किया गया इकबालिया बयान किसी भी अन्य अपराध के लिए स्वीकार्य बना रहेगा। अधिनियम की धारा 12 के तहत टाडा अपराधों के साथ मुकदमा चलाया गया था, इसके बावजूद कि आरोपी को उसी मुकदमे में टाडा के तहत अपराधों से बरी कर दिया गया था।

प्रस्तुतीकरण का दूसरा चरण अधिनियम की धारा 18 की कठोरता है। धारा 18 मामलों को नियमित अदालतों में स्थानांतरित करने की शक्ति से संबंधित है। यह पढ़ता है:–

"जहां, किसी अपराध का संज्ञान लेने के बाद, एक नामित न्यायालय की राय है कि अपराध उसके द्वारा विचारणीय नहीं है, तो वह, इस बात के बावजूद कि उसके पास ऐसे अपराध का मुकदमा चलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, ऐसे अपराध के विचारण के लिए मामले को संहिता के तहत क्षेत्राधिकार रखने वाली किसी भी न्यायालय में स्थानांतरित कर देगा और जिस अदालत में मामला स्थानांतरित किया गया है वह अपराध की सुनवाई इस तरह से आगे बढ़ा सकती है जैसे कि उसने अपराध का संज्ञान लिया हो।"

(जोर दिया गया)

यह तर्क दिया गया है कि अधिनियम की धारा 18 में प्रयुक्त शब्द, "संज्ञान लेने के बाद"में परीक्षण का कोई भी चरण शामिल होगा, जिसमें वह चरण भी शामिल होगा जब निर्णय दिया जाना है। यह प्रस्तुतिकरण भी ग़लत है। यदि विधायिका की मंशा यही रही होती तो वे ऐसा कह सकते थे। विधायिका जानबूझकर "किसी भी अपराध का संज्ञान लेने के बाद"शब्दों का उपयोग करती है, जिसका अर्थ है कि धारा 18 केवल उस चरण पर लागू होगी जहां नामित न्यायालय अपराध का संज्ञान लेता है, यानी जांच पूरी होने और आरोप पत्र दायर होने के बाद। सीआरपीसी की धारा 209 के प्रावधान जिस पर अपीलकर्ताओं के वकील ने भरोसा करने की मांग की, वह धारा 18 के अनुरूप नहीं है। धारा 209 सीआरपीसी में शब्द "संज्ञान लेने के बाद"स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है। धारा 18

एक फ़िल्टर किया गया प्रावधान है। यह धारा केवल उस चरण में लागू होती है जब नामिंत न्यायालय अपराध का स ज्ञान लेता है। यह संज्ञान लेने के चरण में है, नामित न्यायालय से एकत्र किए गए दस्तावेजों और सबूतों को स्कैन करने की उम्मीद की जाती है। इसके साथ ही, यदि नामित न्यायालय की राय है कि अपराध उसके द्वारा विचारणीय नहीं है, तो वह, इस बात के बावजूद कि उसके पास ऐसे अपराध का मुकदमा चलाने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है, ऐसे अपराध के परीक्षण के लिए मामले को संहिता के तहत अधिकार क्षेत्र वाले किसी भी न्यायालय में स्थानांतरित कर देगा। और जिस न्यायालय में मामला स्थानांतरित किया गया है वह अपराध की सुनवाई ऐसे आगे बढ़ा सकता है जैसे कि उसने अपराध का संज्ञान लिया हो। हमारे विचार में, धारा 18 में प्रयुक्त भाषा में कोई अस्पष्टता नहीं है। यदि वकील की दलीलें अपीलकर्ता के लिये, को स्वीकार किया जाता है, यह क़ानून में कुछ पढ़ने जैसा होगा जो वहां नहीं है।

ऐसा कहने के बाद, हम पैराग्राफ 352 (एससीसी पृष्ठ 707) में करतार सिंह (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय की सावधानी के नोट पर भी ध्यान देते हैं: –

> "352. यह सच है कि कई मौकों पर, हमारे सामने ऐसे मामले आए हैं जिनमें अभियोजन पक्ष अनुचित तरीके से टाडा अधिनियम के प्रावधानों को आरोपी व्यक्तियों को जमानत से वंचित करने के उद्देश्य से लागू करता है और कुछ मौकों पर जब अदालतें सामान्य आपराधिक कानून के तहत दर्ज मामलों में जमानत देने के लिए इच्छुक होती हैं, अदालतों के अधिकार को दरकिनार करने के लिए जांच अधिकारी टाडा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करते हैं। ऐसे मामलों में, टाडा के प्रावधानों का इस प्रकार का आह्वान, जिनके तथ्यों की पुष्टि नहीं होती है, पुलिस द्वारा अधिनियम के सरासर दुरूपयोग है और दुरूपयोग के अलावा और कुछ नहीं। जब तक कि सरकारी वकील मौके पर नहीं आते और यह ध्यान में रखते हुए अपनी कठिन जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करते कि वे जनता की ओर से अभियोजक हैं, पुलिस की ओर से नहीं और जब तक नामित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अपने न्यायिक कार्यों का निर्वहन, मौलिक अधिकारों, विशेष रूप से प्रत्येक नागरिक के व्यक्तिगत अधिकार और स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए नहीं करते हैं, जैसा कि संविधान में निहित है, जिसके लिए उन्हें प्रहरी की भूमिका सौंपी गई है, यह नहीं कहा जा सकता है कि टाडा अधिनियम के प्रावधान को विधायी मंशा के अनुरूप प्रभावी ढंग से लागू किया गया है।"

(जोर दिया गया)

हमारे विचार में उपरोक्त टिप्पणी पुलिस अधिकारियों के साथ–साथ नामित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को अधिनियम के दुरुपयोग से सावधान करने और इस अधिनियम को प्रभावी ढंग से और विधायी इरादे के साथ संगत रूप से लागू करने के लिए पर्याप्त है, जिसका अर्थ है विवेकशीलता के बाद हम वही दोहराते हैं।

उपरोक्त कारणों के लिए, संदर्भ का उत्तर उपरोक्त तरह से दिया गया है। अपीलों को अब सुनवाई के लिए नियमित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा।

रेफरेंस का उत्तर दिया गया।